Drishti IAS

करेंट अफेयर्स मध्य प्रदेश

जुलाई 2023

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

मध्य प्रदेश

- ➢ एशियन गेम्स और आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप और आशी चौकसे का चयन 4
- ➢ मध्य प्रदेश 4
- ➢ प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के शहडोल में 'राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन' का शुभारंभ किया 5
- ➢ भोपाल के आर्यन ने जीता स्विमिंग में काँस्य पदक 6
- ➢ मध्य प्रदेश की मंत्रि परिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय 6
- ➢ आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता के मानदेय में वृद्धि का अनुसमर्थन 6
- ➢ मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना 7
- ➢ 30 एकड़ में बन रहा है प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क 7
- ➢ माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड एवं संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास के गठन की स्वीकृति 8
- ➢ खेलो एमपी यूथ गेम्स-2023 सितंबर से होंगे शुरू 8
- ➢ मध्य क्षेत्र कंपनी द्वारा नवीन विद्युत कनेक्शन के लिये 'सरल संयोजन पोर्टल'शुरू 9
- ➢ राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की डॉक्यूमेंट्री 'प्रदीप्ति' लोकार्पित 9
- ➢ क्रिस्प को मिली एआईसीटीई से मान्यता 10
- ➢ एशियन गेम्स-2022 में अब तक मध्य प्रदेश अकादमी के 25 खिलाड़ियों का चयन 10
- ➢ स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने घोषित किये कायाकल्प अवार्ड 11
- ➢ मध्य प्रदेश में स्थापित होगी देश की पहली ई-स्पोर्ट्स अकादमी 12
- ➢ मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय 13
- ➢ मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति-2023 का अनुमोदन 13
- ➢ खातियार गिर को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा 14
- ➢ मुख्यमंत्री ने किया 'विकास पर्व' के लोगो का विमोचन 15
- ➢ आयुष विभाग की 5 सेवाएँ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 16
- ➢ मध्य प्रदेश ने अब तक के सबसे अधिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी की घोषणा की 16
- ➢ राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने प्रदेश के सचिव राजस्व एवं आयुक्त भू-अभिलेख और 15 ज़िलों के कलेक्टर्स को 'भूमि सम्मान 2023' प्रदान किये 17
- ➢ मेपकॉस्ट एवं एनआईएफ गांधीनगर के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर: मध्य प्रदेश में बनेगा स्टेट इनोवेशन फाउंडेशन 18
- ➢ मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के लिये आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया 19
- ➢ राज्यपाल ने 'चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश'संस्करण के तहत प्रदेश के 16 उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया 20
- ➢ नागदा बनेगा प्रदेश का नया ज़िला 21
- ➢ म.प्र. राज्य जूनियर ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 27 जुलाई से 7 अगस्त तक 22
- ➢ पचमढ़ी मैराथन के पाँचवें संस्करण का हुआ सफल आयोजन 22
- ➢ 5वाँ हेलिकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन खजुराहो में आयोजित किया जाएगा 23
- ➢ एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना से 218.98 मेगावाट विद्युत क्रय करने का किया अनुबंध 24

नोट :

- फिट इंडिया क्विज 2022 में शिवपुरी पब्लिक स्कूल के दो छात्र हुए सम्मानित 26
- भोपाल में बनेगा राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय 27
- प्रदेश में लॉजिस्टिक पार्क, फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण, रेलवे वेगन निर्माण और पीवीसी केंद्रित इकाइयों की स्थापना के प्रस्ताव 28
- मध्य प्रदेश के खजुराहो में तीन उड़ान प्रशिक्षण संगठनों का उद्घाटन 29
- खजुराहो में हेलीशिखर सम्मेलन 2023 और उड़ान 5.2 का उद्घाटन 30
- म.प्र. के 11 खिलाड़ी करेंगे चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व 30
- म.प्र. श्रम कल्याण मंडल के संचालक मंडल का गठन 31
- मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय बढ़कर 1,40,583 रुपए हुई 32
- मध्य प्रदेश एक बार फिर बना टाइगर स्टेट 33
- राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी प्रशिक्षण के लिये ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस रवाना 34

नोट :

मध्य प्रदेश

एशियन गेम्स और आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप और आशी चौकसे का चयन

चर्चा में क्यों?

2 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चीन में सितंबर 2023 में शुरू होने वाले एशियन गेम्स और बाकू अजरबैजान में अगस्त में होने वाली आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के दो निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और आशी चौकसे का चयन भारतीय टीम में हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- खरगोन जिले के ऐश्वर्य प्रताप सिंह 10 मीटर एयर राइफल एवं 50 मीटर थ्री पोजीशन मेन तथा भोपाल की आशी चौकसे 10 मीटर एयर राइफल एवं 50 मीटर थ्री पोजीशन वुमेन इवेंट में सेलेक्ट हुए हैं।
- विदित है कि 22 वर्षीय युवा भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने फरवरी 2023 में काहिरा में आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में स्वर्ण पदक तथा जुलाई 2022 में साउथ कोरिया में आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था।
- ऐश्वर्य ने साल 2021 में दिल्ली में हुए विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पॉजिशन इवेंट में पीला तमगा हासिल किया था। फाइनल मुकाबले में ऐश्वर्य ने तत्कालीन वर्ल्ड नंबर-1 हंगरी के इस्त्वान पेनी को मात दी थी।
- 21 वर्षीय आशी चौकसे ने जून 2022 में अजरबेजान के बाकू में आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन मिक्स्ड इवेंट में स्वप्निल कुसाले के साथ स्वर्ण पदक जीता था। आशी ने जर्मनी में हुई आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में काँस्य पदक जीता था।
- इससे पहले आशी बेंगलुरू में हुई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में एक गोल्ड और एक सिल्वर और राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में दो गोल्ड और दो सिल्वर मैडल जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आई थीं।

प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के शहडोल में 'राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन' का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों ?

1 जुलाई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में 'राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन' का शुभारंभ किया और लाभार्थियों को सिकल सेल आनुवंशिक स्थिति कार्ड वितरित किये।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई सी. पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, केंद्रीय राज्य मंत्री, संसद सदस्य, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और विधान सभा के सदस्य भी उपस्थित थे।
- इस मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना है। यह लॉन्च; सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में 2047 तक सिकल सेल रोग को खत्म करने के सरकार के चल रहे प्रयासों का एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
- केंद्रीय बजट 2023 में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन की घोषणा की गई थी। इसे देश के 17 सर्वाधिक प्रभावित राज्यों- गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार और उत्तराखंड के 278 ज़िलों में लागू किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में लगभग 3.57 करोड़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) कार्डों के वितरण कार्यक्रम की भी शुरुआत की। आयुष्मान कार्ड वितरण समारोह का आयोजन प्रदेश भर के नगर निकायों, ग्राम पंचायतों और विकासखंडों में किया जा रहा है।
- आयुष्मान कार्ड वितरण अभियान कल्याणकारी योजनाओं की 100 प्रतिशत संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक लाभार्थी तक पहुँचाने के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने की दिशा में एक कदम है।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का यह अभियान अमृत काल का एक प्रमुख मिशन बनेगा। उन्होंने 2047 तक आदिवासी समुदायों और देश को सिकल सेल एनीमिया के खतरे से मुक्त करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया।

भोपाल के आर्यन ने जीता स्विमिंग में काँस्य पदक

चर्चा में क्यों ?

3 जुलाई, 2023 को हैदराबाद में खेली जा रही 76वीं स्विमिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आर्यन एस गणेश ने काँस्य पदक जीता।

प्रमुख बिंदु

- आर्यन ने यह पदक 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में 705 पाइंट के साथ प्राप्त किया।
- इस इवेंट में सर्विसेज के लिखित एसपी ने स्वर्ण पदक तथा वैष्णव हेगड़े बी ने रजत पदक प्राप्त किया।
- यह पदक भोपाल के किसी भी तैराक का सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में पहला पदक है।

मध्य प्रदेश की मंत्रि परिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

4 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद द्वारा कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रि परिषद द्वारा धार ज़िले की बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिये लागत राशि 478 करोड़ 88 लाख रुपए, सिंचाई क्षमता 15031 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना से कुक्षी तहसील के 43 ग्रामों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
- मंत्रि परिषद ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना का क्रियान्वयन राजस्व विभाग द्वारा किये जाने एवं परियोजना के लिये प्रस्तावित केंद्र प्रवर्तित योजना के अनुसार राज्य शासन द्वारा कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
- राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में एक ही वर्ग की 2 जातियाँ, कुड़मी एवं कुर्मी, कुरमी पृथक्-पृथक् क्रमांक में दर्ज होने के कारण होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिये बुंदेलखंडीय गौर समाज द्वारा माँग की गई थी। इस पर विभागीय प्रस्ताव अनुसार मंत्रि परिषद द्वारा विचारोपरांत कुड़मी जाति को सूची क्रमांक 76 से विलोपित कर सूची क्रमांक 39 में कुर्मी, कुरमी के साथ शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया।
- इस निर्णय से इस वर्ग को जाति प्रमाण-पत्र में आ रही समस्याओं के समाधान के साथ राज्य शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग को प्रदाय किये जा रहे लाभ प्राप्त करने के लिये समान एवं समुचित अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता के मानदेय में वृद्धि का अनुसमर्थन

चर्चा में क्यों ?

4 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता को 3 हज़ार रुपए वृद्धि के बाद अब 13 हज़ार रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा और सहायिका एवं मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता को 750 रुपए वृद्धि के बाद प्रतिमाह बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा।

प्रमुख बिंदु

- आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता के मानदेय में प्रतिवर्ष 1000 और आँगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता के मानदेय में 500 रुपए प्रतिवर्ष की वृद्धि की जाएगी।

नोट :

- इसके साथ ही 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति के समय आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को एक लाख 25 हज़ार रुपए और आँगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आँगनवाड़ी कार्यकत्ताओं को एक लाख रुपए दिये जाएंगे।
- मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में 10 नवीन महाविद्यालय की स्थापना, 4 महाविद्यालयों में नवीन संकाय तथा 7 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर विषय प्रारंभ किये जाने के लिये 589 नवीन पद सृजित करने की मंजूरी दी गई।
- इसके लिये आवर्ती व्यय भार 33 करोड़ 47 लाख 50 हज़ार रुपए प्रतिवर्ष एवं अनावर्ती व्यय 105 करोड़ 46 लाख 70 हज़ार रुपए की स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना

चर्चा में क्यों?

4 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रवींद्र भवन, भोपाल में आईटीआई उत्तीर्ण राज कुशवाह का स्वयं योजना के पोर्टल पर पंजीयन कराकर 'मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी योजना का लाभ ले सकेंगे। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में 18 से 29 वर्ष के युवा पात्र होंगे।
- इस योजना में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण को 8 हज़ार रुपए, आईटीआई उत्तीर्ण को 8 हज़ार 500, डिप्लोमा उत्तीर्ण को 9 हज़ार रुपए, स्नातक या उच्च शिक्षित को 10 हज़ार रूपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी।
- युवाओं को रोज़गार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने के लिये 700 कोर्सेस चयनित किये गए हैं। इसमें सभी प्रकार के उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सर्विस सेक्टर आदि को शामिल किया गया है। पोर्टल पर युवा अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार गतिविधि चुन सकेंगे।
- समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी आवश्यक है। पंजीयन के लिये मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी जरूरी है और बैंक खाता आधार से लिंक हो एवं डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर में सक्षम होना चाहिये।
- इस योजना में अब तक 10 हज़ार 432 प्रतिष्ठानों ने पंजीयन करा लिया है और 34 हज़ार 785 वेकेंसी चिह्नित हैं। प्रदेश के साथ ही प्रदेश के बाहर के प्रतिष्ठानों को भी योजना से जोड़ा जा रहा है।
- 'मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना' व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और युवाओं के हितों को समान रूप से ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इससे युवाओं को काम सीखने का मौका मिलेगा और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को स्किल्ड मेनपावर की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

30 एकड़ में बन रहा है प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क

चर्चा में क्यों?

5 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भोपाल के नरेला शंकरी में प्रदेश के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण तेजी से चल रहा है।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्लोबल स्किल पार्क (जीएसपी) मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आगामी सिंतबर तक जीएसपी पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य है।
- सिंगापुर के सहयोग से बन रहे इस ग्लोबल स्किल पार्क में युवाओं को बेहतर और आधुनिक तकनीकी स्किल्स सिखाकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि लगभग 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 30 एकड़ में बन रहे संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में 6 हज़ार युवाओं को प्रति वर्ष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

नोट :

- जीएसपी में युवाओं को मेकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, एग्रीकल्चर, रेफ्रिजरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस आदि ट्रेड का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड एवं संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास के गठन की स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

4 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की 22 अप्रैल, 2023 की घोषणा के आधार पर पाल-गडरिया, धनगर वर्ग के समग्र कल्याण के लिये माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया।
- माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड में 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होंगे। इस बोर्ड के गठन से पाल-गडरिया, धनगर वर्ग के व्यक्तियों के लिये शासन की कल्याणकारी/ जन-हितकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।
- इस वर्ग की आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमों का निर्माण किया जा सकेगा। इससे इस वर्ग के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को गति प्राप्त हो सकेगी।
- इसके साथ ही मंत्रि-परिषद ने मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम अंतर्गत 'संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास' की स्थापना एवं गठन के लिये भी स्वीकृति प्रदान की।

खेलो एमपी यूथ गेम्स-2023 सितंबर से होंगे शुरू

चर्चा में क्यों?

5 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने विभागीय अधिकारियों के साथ खेलो एमपी यूथ गेम्स की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के मंशानुसार सितंबर माह में 'खेलो एमपी यूथ गेम्स-2023' का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पहली बार हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की सफलता के बाद घोषणा की थी कि अब 'खेलो एमपी यूथ गेम्स-2023' का आयोजन किया जाएगा।
- खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि 'खेलो एमपी यूथ गेम्स' सभी 52 ज़िलों में तीन चरणों- ज़िला, संभाग और राज्य स्तर पर होगा।
- 'खेलो एमपी यूथ गेम्स' में 24 खेल- एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो-खो, मलखंब, शूटिंग, तैराकी, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, टेबल-टेनिस, योगासन, ताईक्वांडो, व्हालीबॉल, क्याकिंग-केनोइंग, रोइंग, फेंसिंग, तीरंदाजी, शतरंज और टेनिस में 18 वर्ष से कम आयु के युवा अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
- राज्य स्तर पर एथलेटिक्स एवं शूटिंग प्रतियोगिताएँ स्पोर्ट्स कांपलेक्स शिवपुरी में होगी। भोपाल के टी.टी. नगर स्टेडियम में बाक्सिंग, ताईक्वांडो, जूडो, फेसिंग, टेनिस, बड़ी झील में क्याकिंग कैनोइंग और रोइंग तथा तरण पुष्कर भोपाल में तैराकी प्रतियोगिताएँ होंगी।
- बालाघाट के मुलना स्टेडियम में पुरूष फुटबॉल, इंदौर के बास्केटबॉल काम्पलेक्स में बास्केटबॉल और वेटलिफ्टिंग, अभय प्रशाल में व्हालीबॉल, एमरॉल्ड हाईव्स स्कूल में महिला फुटबॉल प्रतियोगिताएँ होंगी।
- ग्वालियर में म.प्र. बैडमिंटन अकादमी कैंप में बैडमिंटन और म.प्र. महिला हॉकी अकादमी में हॉकी की स्पर्धाएँ होंगी। मलखंब और योगासन प्रतियोगिताएँ स्पोर्टस कॉम्पलेक्स उज्जैन, खो-खो और तीरंदाजी जबलपुर के रानीताल स्पोर्ट्स काम्पलेक्स (क्रिकेट स्टेडियम) में होंगे।
- स्पोर्ट्स काम्पलेक्स रीवा में कबड्डी, कटनी के इंडोर हॉल माधव नगर में टेबल-टेनिस एवं शतरंज और खंडवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में कुश्ती की प्रतियोगिताएँ होंगी।

नोट :

- व्यक्तिगत खेलों में प्रथम स्थान पाने वाले खिलाड़ी को 51 हज़ार, द्वितीय को 31 हज़ार तथा तृतीय स्थान के विजेता को 21 हज़ार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
- दलीय खेलों में प्रथम स्थान के विजेता को 5 लाख, द्वितीय स्थान के विजेता को 3 लाख और तृतीय स्थान के विजेता को 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
- खेल मंत्री सिंधिया ने बिशनखेड़ी स्थित मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी में निर्माणाधीन फाइनल रेंज के कार्यों का जायजा लेते हुए कहा कि एनआरएआई के तकनीकी सहयोग से निर्मित फाइनल रेंज अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करेगा।
- उन्होंने कहा कि आईएसएसएफ के अध्यक्ष लूसियानो रौसी ने भोपाल प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी को दुनिया की सबसे खूबसूरत और सर्वसुविधायुक्त शूटिंग रेंज का दर्जा दिया था।

मध्य क्षेत्र कंपनी द्वारा नवीन विद्युत कनेक्शन के लिये 'सरल संयोजन पोर्टल' शुरू

चर्चा में क्यों ?

5 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को नवीन बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु 'सरल संयोजन पोर्टल' को शुरू किया है।

प्रमुख बिंदु

- कंपनी द्वारा इस पोर्टल से अभी तक 10 आवेदकों को समस्त प्रक्रियाएँ पूर्ण कर आवश्यक दस्तावेज़ों सहित नये बिजली कनेक्शन के लिये ऑनलाइन आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर ही नया बिजली कनेक्शन दे दिया गया है।
- इस पोर्टल से आवेदन अपूर्ण होने की स्थिति में कंपनी द्वारा आवेदक को एसएमएस से आवेदन पूर्ण करने का एक अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। उपभोक्ता द्वारा इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के बाद उसकी स्थिति को भी देखा जा सकेगा एवं उपभोक्ता को नया कनेक्शन लेने के लिये कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।
- ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को नया बिजली कनेक्शन सुगमता से मिले इसके लिये कंपनी द्वारा नवीन पोर्टल 'सरल संयोजन पोर्टल' का क्रियान्वयन शुरू कर विधिवत पूर्ण आवेदन पर बहुत ही कम समय में नवीन कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
- अब उपभोक्ताओं को नवीन कनेक्शन के आवेदन के लिये सभी जरूरी जानकारी भरने के साथ ही डिमांड नोट का ऑनलाइन भुगतान करने बाद अनुबंध की शर्तें दिखाई देंगी, जिन्हें स्वीकार करने पर पोर्टल में स्वत: ही अनुबंध क्रियान्वित हो जाएगा।
- आवेदकों को इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के साथ स्वयं का फोटो, पहचान पत्र, स्वामित्व संबंधी दस्तावेज़ तथा टेस्ट रिपोर्ट आदि अपलोड करना आवश्यक होगा।
- इस पोर्टल से आवेदक को अपूर्ण आवेदन होने की स्थिति में रिजेक्शन होने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क के अतिरिक्त अन्य जमा शुल्क राशि ऑनलाइन माध्यम से खाते में तुरंत वापस कर दी जाएगी।

राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की डॉक्यूमेंट्री 'प्रदीप्ति' लोकार्पित

चर्चा में क्यों ?

9 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार कराई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'प्रदीप्ति' का राजभवन में लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को जागरूक कर परीक्षा के भय को कम करने का प्रयास सराहनीय है। आयोग द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री इस दिशा में अभिनव और अनुकरणीय पहल है।

नोट :

- राज्यपाल ने कहा कि परीक्षा की तैयारियों के संबंध में आयोग द्वारा तैयार वृत्तचित्र अभ्यर्थियों को परीक्षा के भय से मुक्त करेगा। अभ्यर्थियों की जागरूकता बढ़ने से आयोग की कार्य-प्रणाली और अधिक पारदर्शी होगी।
- मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राजेश लाल मेहरा ने बताया कि डाक्यूमेंट्री 'प्रदीप्ति' में आयोग की विभिन्न परीक्षाओं तथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को जागरूक करने के लिये परीक्षा संबंधी नियमों एवं निर्देशों की जानकारी दी गई है।
- विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में प्राय: यह देखने में आता रहा है कि अनेक परीक्षार्थी कुछ न कुछ गलतियाँ करते रहते हैं और उन्हें सुधारने के लिये पत्राचार करते हैं। उन्हें आयोग की कार्य-प्रणाली का भी समुचित ज्ञान नहीं होता। पूर्णत: परीक्षार्थी केंद्रित यह डॉक्यूमेंट्री इस दिशा में उनकी सहयोगी होगी।
- डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षार्थियों को परीक्षा संबंधी विभिन्न जानकारियाँ देकर प्रशिक्षित करना है। डॉक्यूमेंट्री में अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा पूर्व किये जाने वाले कार्यों, परीक्षा के दौरान की सावधानियों, साक्षात्कार संबंधी सूचनाओं और साक्षात्कार के बाद उपयोगी जानकारियों को विस्तार से बताया गया है।

क्रिस्प को मिली एआईसीटीई से मान्यता

चर्चा में क्यों ?

8 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश की अग्रणी संस्था क्रिस्प को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से 'पोस्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम' की मान्यता प्राप्त हुई है।

प्रमुख बिंदु

- यह मान्यता फिलहाल दो शैक्षणिक सत्र 2023-24 और 2024-25 के लिये मिली है, जिसमें डेढ़ साल के 'पोस्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम' की मान्यता मिली है। इसके लिये औपचारिक प्रवेश प्रक्रिया 1 अगस्त, 2023 से शुरू होगी और 1 सितंबर से भोपाल परिसर में कक्षाएँ भी शुरू हो जाएंगी।
- गौरतलब है कि क्रिस्प मध्य प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत एक स्वशासी संस्था है। क्रिस्प अब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मेकाट्रोनिक्स, मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस- मशीन लर्निंग), इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (कंप्यूटर एप्लीकेशन), हाई-टेक टेक्नोलॉजी (कंप्यूटर एप्लीकेशन) जैसे विशेष हाई-टेक पोस्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेट संचालित करेगा।
- प्रस्तावित पाठ्यक्रम उम्मीदवारों को 100 प्रतिशत प्लेसमेंट प्रदान करेंगे।
- क्रिस्प के निदेशक अमोल वैद्य ने बताया कि एआईसीटीई से मान्यता के बाद क्रिस्प को एफ.डी.पी, टी.ओ.टी के आयोजन और इंक्यूबेशन सेंटर, उद्योग 4.0 केंद्र स्थापित करने में मदद मिलेगी। साथ ही आईओटी, ए.आई और एम.एल जैसे भविष्योन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू करने में मदद मिलेगी।

एशियन गेम्स-2022 में अब तक मध्य प्रदेश अकादमी के 25 खिलाड़ियों का चयन

चर्चा में क्यों ?

8 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चीन के हांग्जो में होने वाले 19वीं एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश खेल अकादमी के 25 खिलाड़ियों ने अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। अब तक वाटर स्पोर्ट्स, शूटिंग, घुड़सवारी, एथलेटिक्स के खिलाड़ी शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि आगामी 23 सितंबर से 8 अक्तूबर तक चीन के हांग्जो में 19वीं एशियन गेम्स-2022 की शुरुआत होगी।
- कोविड-19 की वजह से एशियन गेम्स को स्थगित किया गया था। इन एशियन खेलों में एक बार पुन: मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अपनी पूरी तैयारी के साथ भारत का परचम लहराने के लिये तैयार हैं।

- एशियन गेम्स में चयनित खिलाड़ी
- मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के शुभम केवट, विश्वजीत सिंह कुशवाह, कु. शिखा चौहान, कु. आहना यादव, केनो स्लालम में भारतीय टीम के लिये चयनित हुए हैं।
- कु. नेहा ठाकुर, कु. शीतल वर्मा, कु. हर्षिता तोमर- सेलिंग; अर्जुन सिंह, नीरज वर्मा, नितिन वर्मा, कु. शिवानी वर्मा, कु. कावेरी, कु. ओ. बिनीता देवी क्याकिंगकेनोइंग में एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- रोइंग में मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की कु. रूक्मिणी दांगी और अकादमी की पूर्व खिलाड़ी कु. अंशिका भारती का चयन किया गया है।
- वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की ही पैरा केनो के खिलाड़ी कु. प्राची यादव और मनीष कौरव भारतीय क्याकिंग केनोइंग टीम का हिस्सा होंगे।
- म.प्र. राज्य घुड़सवारी अकादमी के स्टार घुड़सवार राजू सिंह एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट अकादमी के शंकर पांडे फेंसिंग के ई.पी एकल और टीम इवेंट में भारतीय टीम में शामिल होंगे।
- मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और कु. आशी चौकसे रायफल शूटिंग में और अकादमी की ही कु. मनीषा कीर शॉटगन ट्रेप इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। साथ ही कु. प्रीति रजक, जो अकादमी की पूर्व खिलाड़ी रही हैं, शॉटगन के ट्रेप इवेंट में भारतीय टीम में शामिल होंगी।
- मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की एसोसिएट मेंबर रहीं कु. दीक्षा 1500 मीटर में तथा कु. सपना बर्मन हेप्थलॉन इवेंट में 19वीं एशियन गेम्स भारतीय एथलेटिक्स टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने घोषित किये कायाकल्प अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

10 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने वर्ष 2023 के कायाकल्प अवार्ड की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी ज़िला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अवार्ड की जानकारी देते हुए डॉ. चौधरी ने कहा कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में दोगुने से अधिक संस्थाओं को कायाकल्प अवार्ड दिये जाएंगे।
- स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि वर्ष 2022 में 395 संस्थाओं को 4 करोड़ 50 लाख रुपए के कायाकल्प अवार्ड दिये गए थे। इस वर्ष 778 संस्थाओं को 6 करोड़ 12 लाख रुपए के कायाकल्प अवार्ड दिये जाएंगे।
- अवार्ड की कुल राशि में से 75 प्रतिशत राशि संस्था के सुदृढ़ीकरण में उपयोग में लाई जाती है और 25 प्रतिशत राशि संस्थाओं के कर्मचारियों को इंसेंटिव के रूप में दी जाती है।
- स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने ज़िला अस्पताल अनूपपुर और रतलाम को संयुक्त रूप से 25-25 लाख रुपए का प्रथम कायाकल्प अवार्ड देने की घोषणा की।
- प्रथम रनरअप ज़िला अस्पताल सीहोर को 20 लाख रुपए और द्वितीय रनरअप ज़िला अस्पताल दमोह को 10 लाख रुपए के अवार्ड दिये जाने की घोषणा की।
- बेस्ट ईको-फ्रेंडली ज़िला अस्पताल विदिशा को 10 लाख रुपए के अवार्ड दिये जाने की घोषणा की गई।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर ज़िला सतना को सिविल अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की श्रेणी में 15 लाख रुपए का पहला और बेस्ट ईको-फ्रेंडली चिकित्सालय का 5 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की गई।
- सिविल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की श्रेणी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जावर ज़िला सीहोर को 10 लाख रुपए का रनरअप कायाकल्प अवार्ड देने की घोषणा की गई।

नोट :

- प्रदेश के 43 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को प्रथम कायाकल्प अवार्ड देने की घोषणा की गई। इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कनाड़ (आगर-मालवा), उबलार (अलीराजपुर), भानेगाँव (बालाघाट), भवाती (बड़वानी), देहरी अमढाना (बैतूल), मिहोना (भिंड), नजीराबाद (भोपाल), निम्बोला (बुरहानपुर), गढ़ी-मलहरा (छतरपुर), मांगुरली (छिंदवाड़ा), जेरथ (दमोह), सोनागिर (दतिया), बैजगवाड़ा (देवास), गढ़ासारसी (डिंडोरी), मकसूदनगढ़ (गुना), चिनोर (ग्वालियर), रहटगाँव (हरदा), क्षिप्रा (इंदौर), गोसलपुर (जबलपुर), काकनवानी (झाबुआ), पुरनी (खंडवा), करही और बांगरदा (खरगोन), समनापुर (मंडला), टकरवाड़ (मंदसौर), सुमावली (मुरैना), सेमरी हरचंद (नर्मदापुरम), सिंगपुर (नरसिंहपुर), डिकेन (नीमच), देवनगर (रायसेन), माचलपुर (राजगढ़), धारड़ (रतलाम), रेहट (रीवा), जैतवाड़ा (सतना), वीरपुर डेम (सीहोर), पलारी (सिवनी), टेहकी (शहडोल), मक्सी (शाजापुर), दुर्गापुरी (श्योपुर), लुकवासा (शिवपुरी), उन्हेल (उज्जैन), करकेली (उमरिया) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुलाबगंज (विदिशा) शामिल हैं।
- शहरी स्वास्थ्य केंद्र में संभाग स्तर पर प्रथम पुरस्कार के लिये मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक पिपलानी (भोपाल), सुभाष नगर (इंदौर), गोल पहाड़िया (ग्वालियर), उज्जैन संभाग से इटावा (देवास), जबलपुर संभाग में कोलीपाथर (जबलपुर), रीवा संभाग से हनुमान नगर (सतना) और सागर संभाग से शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मकरोनिया को पुरस्कार देने की घोषणा की गई।
- हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर श्रेणी में 30 संस्थाओं को विनर घोषित किया गया। इनमें रायपुर (भोपाल), पनवारी (छतरपुर), गढ़ाघाट (जबलपुर), कुचवाही (सीधी), पिचोड़ी (बड़वानी), बंडीखुर्द (शहडोल), कजलाना (इंदौर), छिपोन (गुना), अमलाई (अनूपपुर), बिलढाना (विदिशा), नन्हीं टेहरी (टीकमगढ़), चांदनिया (उमरिया), बगवाड़ा (सीहोर), बरखेड़ा सेतु (रायसेन), गोरही (सतना), सेजी (अशोकनगर), निगोरी (डिंडोरी), पंजरकाला (नर्मदापुरम), अहमदपुर खैगाँव (खंडवा), हिरनखेड़नी (राजगढ़), इच्छापुर (बुरहानपुर), पटना बुजुर्ग (सागर), रूपगढ़ (झाबुआ), मकडाबदा (श्योपुर), डबाडी (अलीराजपुर), नरसिंहगढ़ (दमोह), इंदरी (मंडलाला), बड़ागाँव (पन्ना), सिद्धिकला (सिंगरोली) और बोटलगंज (मंदसौर) को पुरस्कार देने की घोषणा की गई।
- विजेता संस्थाओं के अतिरिक्त मानदंडों के अनुरूप 70 प्रतिशत से अधिक स्कोर करने वाली संस्थाओं को सांत्वना पुरस्कार दिये जाने की घोषणा भी की गई।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के प्रयासों की श्रृंखला में कायाकल्प अवार्ड एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के अनुक्रम में प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थाओं में साफ-सफाई रखने और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिये वर्ष 2015 से कायाकल्प अवार्ड प्रारंभ किये गए।
- अस्पतालों के परिसर में साफ-सफाई रखने और स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने की गुणवत्ता की विशेषज्ञों के दल द्वारा जाँच के बाद निर्धारित मानदंड अनुसार स्वास्थ्य संस्थाओं को नंबर दिये जाते हैं। सर्वाधिक नंबर पाने वाले अस्पताल को प्रथम पुरस्कार के लिये चयनित किया जाता है।
- ज़िला अस्पताल, सिविल/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की 5 श्रेणी में कायाकल्प अवार्ड दिये जाते हैं।

मध्य प्रदेश में स्थापित होगी देश की पहली ई-स्पोर्ट्स अकादमी

चर्चा में क्यों ?

12 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने मध्य प्रदेश में देश की पहली ई-स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- खेल मंत्री ने बताया कि इसके लिये 23 जुलाई से 27 अगस्त तक मध्य प्रदेश राज्य जूनियर ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के माध्यम से टेलेंट सर्च किया जाएगा। दस दिनों के इस टूर्नामेंट में 12-17 आयु वर्ग के युवा प्रतिभागिता करेंगे।
- मध्य प्रदेश में दो ऐसे खेलों को आगे बढ़ाने का निर्णय गया लिया है, जो आगामी ओलंपिक और एशियन गेम्स में शामिल हैं। इसमें सबसे पहले हर ज़िले में टेलेंट सर्च के माध्यम से पेरिस ओलंपिक में शामिल ब्रेक डांसिंग प्रतिभाओं को खोजने का कार्य किया जा रहा है।
- ई-स्पोर्ट्स को भी कांपेटेटिव स्पोर्ट्स के रूप में पदक जीतने वाले खेल की श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में शामिल किया गया है। इसमें बर्मिंघम में वर्ष 2022 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय टीम ने काँस्य पदक हासिल किया था। सितंबर में शुरू होने वाले एशियन गेम्स में भी ई-स्पोर्ट्स शामिल है।

नोट :

- खेल मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश खेलों के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हुआ है। प्रदेश में ब्रेक डांस और ई-स्पोर्ट्स अकादमी देश में पहली ऐसी अकादमी होगी जो युवाओं को पारंपरिक खेलों के अतिरिक्त इन खेलों में भी अपने हुनर को निखारने का मौका देगी। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में ई-स्पोर्ट्स को शामिल करने से भारत के युवा खिलाड़ियों को अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने का मौका मिलेगा।

मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

12 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद ने महिला स्व-सहायता समूह द्वारा उपभोक्ता शुल्क संग्रहण के लिये नीति का अनुमोदन करने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रि-परिषद ने महिला स्व-सहायता समूह द्वारा उपभोक्ता शुल्क संग्रहण के लिये नीति का अनुमोदन किया। मंत्रि-परिषद ने महिला स्व-सहायता समूह को अधिक सक्षम एवं उपभोक्ता शुल्क (टोल) संग्रहण में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये यह निर्णय लिया।
  - निर्णय अनुसार पूर्व में उपभोक्ता शुल्क संग्रहण की स्वीकृति प्राप्त मार्गों में से दो करोड़ से कम वार्षिक संग्रहण आय वाले मार्गों पर उपभोक्ता शुल्क संग्रहण महिला स्व-सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। ऐसे मार्ग का चयन करने के लिये मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को अधिकृत किया गया है।
- मंत्रि-परिषद ने ज़िला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया।
  - ज़िला पंचायत अध्यक्ष के मानदेय एवं वाहन भत्ता को बढ़ाकर 1 लाख रुपए मासिक (मानदेय 35 हज़ार रुपए एवं वाहन भत्ता 65 हज़ार रुपए) और ज़िला पंचायत के उपाध्यक्ष के मानदेय एवं वाहन भत्ता को बढ़ाकर 42 हज़ार रुपए मासिक (मानदेय 28 हज़ार 500 रुपए एवं वाहन भत्ता 13 हज़ार 500 रुपए) किया जाएगा।
  - जनपद पंचायत अध्यक्ष के मानदेय को बढ़ाकर 19 हज़ार 500 रुपए मासिक एवं जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के मानदेय को बढ़ाकर 13 हज़ार 500 रुपए मासिक करने का निर्णय लिया गया।
  - इसके अतिरिक्त पंच/उप सरपंच का अधिकतम वार्षिक मानदेय 1800 रुपए किया जाएगा।
- मंत्रि-परिषद ने ग्राम रोज़गार सहायक के भरे पद एवं रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने पर 18 हज़ार रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय के लिये आवश्यक अतिरिक्त वार्षिक राशि 274 करोड़ 95 लाख रुपए व्यय करने की अनुमति दी। यह राशि स्टांप शुल्क वसूली या गौण खनिज मद से व्यय की जाएगी।
- मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में 8 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना, 2 महाविद्यालयों में नवीन संकाय और 3 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर/स्नातक विषय प्रारंभ करने की मंजूरी दी है।
  - खंडवा ज़िले के खालवा, भोपाल के फंदा, शहडोल के बाणसागर, श्योपुरकलाँ के बड़ौदा, सीधी के मंडवास, इंदौर के बेटमा, रीवा के हनुमना और बालाघाट के हट्टा में नवीन शासकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाएंगे।
  - साथ ही छतरपुर के बिजावर और सीधी के चुरहट में पूर्व से संचालित शासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय प्रारंभ किये जाएंगे।
  - इसके अलावा शासकीय महाविद्यालय रामपुर नैकिन, ज़िला सीधी में आर्ट एंड साइंस, शासकीय महाविद्यालय लामता, ज़िला बालाघाट में आर्ट्स एवं बॉयोलॉजी और शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच में संगीत एवं फाइन आर्ट विषय प्रारंभ किये जाएंगे।

मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति-2023 का अनुमोदन

चर्चा में क्यों ?

12 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के शासकीय सेवकों की क्षमता निर्माण के लिये 'मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति-2023' का अनुमोदन किया। यह नीति राज्य की वर्तमान प्रशिक्षण नीति-2001 का स्थान लेगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राज्य की नवीन क्षमता निर्माण नीति-2023 भारत सरकार द्वारा लागू 'मिशन कर्मयोगी' की अवधारणा एवं विशेषताओं को सम्मिलित करते हुए और क्षमता विकास आयोग के सदस्य से परामर्श प्राप्त करते हुए तैयार की गई है।
- मध्य प्रदेश भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है, जहाँ 'मिशन कर्मयोगी'की अवधारणा के अनुरूप प्रदेश की क्षमता निर्माण नीति को तैयार कर उसे लागू करने का निर्णय लिया गया है।
- विदित है कि भारत सरकार की राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति वर्ष 1996 के संदर्भ में राज्य की वर्तमान प्रशिक्षण नीति को 11 जुलाई, 2001 को लागू किया गया था। भारत सरकार की वर्तमान राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति 19 जनवरी, 2012 को लागू की गई, लेकिन राज्य की प्रशिक्षण नीति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया था।
- प्रदेश की वर्तमान प्रशिक्षण नीति लगभग 22 वर्ष पुरानी हो चुकी है, जबकि शासकीय सेवकों के भर्ती के तरीके, सूचना प्रौद्योगिकी का शासकीय कार्यों में उपयोग, विभिन्न कानूनों में परिवर्तन इत्यादि कारणों से नवीन प्रशिक्षण नीति की आवश्यकता महसूस की गई।
- नवीन नीति में प्रदेश के समस्त शासकीय सेवकों, जिनमें संविदा कर्मी भी शामिल हैं, के संपूर्ण क्षमता निर्माण के लिये प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियाँ की जाएंगी, जिससे शासकीय सेवक गुणवत्तापूर्ण नागरिक सेवा प्रदान करने के लिये संवेदनशील, कर्त्तव्यनिष्ठ, तत्पर, ईमानदार हों तथा आधुनिक तकनीक कौशल से युक्त होकर कार्य कर सकें।
- इस नीति में शासकीय सेवा के प्रत्येक संवर्ग के लिये संपूर्ण सेवाकाल की क्षमता विकास योजना तैयार की जाएगी। योजना के आधार पर शासकीय सेवक निश्चित अंतराल पर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा और उसे पदोन्नति से जोड़ा गया है। नीति में कर्त्तव्यनिष्ठ शासकीय सेवकों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है।
- नीति के अनुसार प्रत्येक विभाग में क्षमता निर्माण इकाई का गठन किया जाना है, जो प्रत्येक पद के उत्तरदायित्व, कार्य और इसके लिये आवश्यक क्षमताओं का निर्धारण कर उसके अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी।
- इसमें बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण की आवश्यकता को देखते हुए 70 प्रतिशत प्रशिक्षण ऑनलाइन, 20 प्रशिक्षण कार्य-स्थल पर और 10 प्रतिशत प्रशिक्षण किसी प्रशिक्षण संस्थान में किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद शासकीय सेवक की कार्य-क्षमता में हुए परिवर्तन का आकलन भी किया जाएगा।
- नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिये सर्वोच्च स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य प्रशिक्षण परिषद गठित होगी, जिसमें मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारी होंगे। परिषद के सदस्य सचिव महानिदेशक प्रशासन अकादमी होंगे। इसके अलावा एक कार्यपालक समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित होगी, जिसमें प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सदस्य तथा संचालक प्रशासन अकादमी सदस्य सचिव होंगे।
- नवीन नीति में राज्य के बजट में 'मिशन कर्मयोगी'नाम से एक नवीन मद बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक शासकीय विभाग को उसके वेतन मद की एक प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जाएगी।
- मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिये आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसके लिये प्रशासन अकादमी को राज्य के बजट से प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपए प्रदान किये जाएंगे।

खातियार गिर को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा

चर्चा में क्यों?

12 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश के पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग की अध्यक्षता में पर्यावरण परिसर में हुई राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की बैठक में चंबल अभयारण्य के खातियार गिर ईको रीजन वेटलैंड को देश के नये रामसर साइट में शामिल करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि प्रदेश में भोज वेटलैंड सहित 4 रामसर साइट हैं। इनमें से इंदौर की यशवंत सागर और सिरपुर तालाब, माधव राष्ट्रीय पार्क शिवपुरी के सांख्य सागर को पिछले वर्ष केंद्र शासन से रामसर साइट का दर्जा मिला है।

नोट :

- केंद्र शासन की एनपीसीए योजना में धार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स (धूपसागर, देवीसागर और मुंजसागर) और गिरवर तालाब शाजापुर की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
- बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले 15 हज़ार से अधिक तालाबों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार किया जा रहा है।
- जल स्रोतों के संरक्षण में समाज, प्रशासन को भागीदार बनाने के उद्देश्य से ज़िला वेटलैंड संरक्षण समितियों का गठन किया जा रहा है। अब तक 22 ज़िलों में इनका गठन हो चुका है।
- इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने मध्य प्रदेश राज्य वेटलैंड प्राधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश की रामसर साइट-भोज वेटलैंड, सांख्य सागर, सिरपुर और यशवंत सागर पर आधारित 'रामसर साईट्स' पुस्तिका का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री ने किया 'विकास पर्व' के लोगो का विमोचन

चर्चा में क्यों?

15 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में 'विकास पर्व' के लोगो का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि 16 जुलाई से 14 अगस्त तक पूरे प्रदेश में एक माह तक विकास पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश के सभी ज़िलों में व्यापक पैमाने पर जन-सेवा यात्राएँ, जन-संवाद, हितग्राही सम्मेलन होंगे। प्रदेश में लगभग 2 लाख करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण/भूमि-पूजन होगा।
- विकास पर्व के दौरान विभिन्न योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री भू-अधिकार, दीनदयाल रसोई, मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन, जल-जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, संबल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी आदि योजनाओं और महिला सशक्तीकरण, युवा कल्याण, स्व-रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन संबंधी योजनाओं के हितग्राही सम्मेलन किये जाएंगे।
- विकास पर्व अवधि में सभी ज़िलों में मंत्री, सांसद, विधायक तथा स्थानीय जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ज़िला, तहसील और ब्लॉक स्तर आदि पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे।

नोट :

- सीएम हेल्पलाइन पर विकास पर्व के लिये तैयार किये गए पोर्टल पर सभी कार्यक्रमों की तिथिवार जानकारी अपलोड होगी। होने वाले सभी भूमि-पूजन/लोकार्पण का पूरा विवरण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।
- विकास पर्व के दौरान प्रमुख लोकार्पण एवं भूमि-पूजन।
  - बीना रिफायनरी का विस्तार और केन-बेतवा लिंक योजना का भूमि-पूजन/शिलान्यास।
  - 7245 करोड़ रुपए की 15 सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण।
  - 36 हजार 348 करोड़ रुपए की 13 सिंचाई परियोजनाओं का भूमि-पूजन।
  - 83 सीएम राइज स्कूलों का शुभारंभ।
  - नव स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों का भूमि-भूजन।
  - राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग एवं सड़क निर्माण के 21 हजार 900 करोड रुपए से अधिक की लागत के 1207 कार्यों का भूमि-पूजन।
  - अमृत 2.0 अंतर्गत शहरी पेयजल परियोजनाओं 3000 करोड़ रुपए की राशि के कार्य।
  - प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग 4 लाख हितग्राहियों का गृह प्रवेश।
  - 10 नवीन महाविद्यालयों का भूमि-पूजन।
  - जल जीवन मिशन की 28 हजार 471 करोड़ रुपए की 15 हजार 450 समूह पेयजल परियोजनाओं का भूमि-पूजन।

आयुष विभाग की 5 सेवाएँ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत

चर्चा में क्यों?

14 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आयुष विभाग में 5 विभागीय सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। इन सेवाओं के लिये समय-सीमा भी तय की गई है।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार जिन सेवाओं को शामिल किया गया है, उनमें आयुष चिकित्सकों का पंजीयन, आयुष चिकित्सकों का प्रोवीजनल पंजीयन, अन्य प्रदेश में पंजीयन के लिये एनओसी जारी किया जाना, आयुर्वेद औषधि निर्माण लायसेंस जारी करने के साथ ही होम्योपैथी औषधि निर्माण लायसेंस जारी करना शामिल हैं।
- इस प्रक्रिया के लिये 30 कार्य-दिवस की समय-सीमा तय की गई है।
- केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत प्रदेश में आयुष मिशन योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य स्तर पर आयुष मिशन सोसायटी का गठन किया गया है।
- आयुष मिशन में आयुष चिकित्सा सुविधा को अधिकतम जन-समुदाय को उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके तहत संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ किया जा रहा है। मिशन में ही उन किसानों को मदद पहुँचाई जा रही है, जो औषधीय पौधों की खेती से जुड़े हुए हैं।
- औषधीय पौधों के उत्पादों का मूल्य संवर्धन, विपणन और औषधीय पौधों से निर्मित होने वाली औषधि उद्यमियों को अधो-संरचना विकास में मदद पहुँचाना भी मिशन का उद्देश्य है।

मध्य प्रदेश ने अब तक के सबसे अधिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

14 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश रिकॉर्ड संख्या में 51 खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिये निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) जारी किया है। यह किसी भी राज्य द्वारा एक ही किश्त में नीलामी के लिये अधिसूचित खनिज ब्लॉकों की सबसे अधिक संख्या है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2015 में नीलामी व्यवस्था प्रारंभ होने के बाद विभिन्न प्रमुख खनिज भंडार वाले राज्यों द्वारा 754 ब्लॉकों को नीलामी के लिये रखा गया है, जिनमें से 276 ब्लॉकों की सफल नीलामी की गई है। भारत सरकार ने इसके लिये मध्य प्रदेश की सराहना की।

नोट :

- इन 51 ब्लॉकों में 14 खनिज शामिल हैं, जिनमें ग्रेफाइट और वैनेडियम, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलीमेंट्स (पीजीई) जैसे रणनीतिक और महत्त्वपूर्ण खनिज तथा मैंगनीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, लौह अयस्क, बेस मेटल और सोना जैसे अन्य प्रमुख खनिज शामिल हैं।
- मध्य प्रदेश द्वारा जिन 51 खनिज ब्लॉकों के लिये एनआईटी जारी की गई है, उनमें से 13 ब्लॉक खनन पट्टे के लिये और 38 ब्लॉक कंपोजिट लाइसेंस के लिये हैं।
- मध्य प्रदेश खनिज ब्लॉक नीलामी के मामले में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भी अन्य राज्यों से सबसे आगे था। उस वित्तीय वर्ष में प्रदेश ने 29 ब्लॉकों की नीलामी की थी।
- वर्ष 2015 में नीलामी व्यवस्था की शुरुआत के बाद से, मध्य प्रदेश ने 125 खनिज ब्लॉकों को नीलामी के लिये अधिसूचित किया है। इनमें से 46 की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है।
- इन 51 ब्लॉकों की अधिसूचना के साथ मध्य प्रदेश नीलामी के लिये अधिसूचित ब्लॉकों की सबसे अधिक संख्या वाले राज्य के रूप में भी उभरा है, जिससे कुल खनिज ब्लॉकों की संख्या 176 हो गई है।
- उल्लेखनीय है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल की राज्य सरकारों ने 2015 के बाद से किसी भी ब्लॉक की नीलामी नहीं की है।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने प्रदेश के सचिव राजस्व एवं आयुक्त भू-अभिलेख और 15 ज़िलों के कलेक्टर्स को 'भूमि सम्मान 2023' प्रदान किये

चर्चा में क्यों?

18 जुलाई, 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में भूमि प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये मध्य प्रदेश के सचिव राजस्व एवं आयुक्त भू-अभिलेख डॉ. संजय गोयल और 15 ज़िलों के कलेक्टर्स को 'भूमि सम्मान 2023' प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यों के सचिवों और 68 कलेक्टर्स को पुरस्कार दिये।
- मध्य प्रदेश राज्य शासन की ओर से सचिव राजस्व एवं आयुक्त भू-अभिलेख डॉ. संजय गोयल एवं अपर सचिव चंद्रशेखर वालिम्बे ने अपनी टीम के साथ पुरस्कार ग्रहण किया।
- डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने राज्य व ज़िला दोनों ही श्रेणियों में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह राज्य व केंद्र सरकार के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ शत-प्रतिशत राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदाय की जाती है, वहीं राज्य सरकारों द्वारा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है।
- कार्यक्रम में प्रदेश के 15 ज़िलों- आगर मालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, भोपाल, गुना, हरदा, इंदौर, खरगौन, नीमच, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया और विदिशा के कलेक्टर्स को भूमि सम्मान प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया गया।
- मध्य प्रदेश के इन ज़िलों द्वारा डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम के सभी घटकों में शत-प्रतिशत उपलब्धि पर उन्हें प्लेटिनम ग्रेडिंग प्रदान की गई है। ये घटक है- लैंड रिकॉर्ड्स का कंप्यूटराइजेशन, भू-कर मानचित्रों का डिजिटाइजेशन, पंजीयन का कंप्यूटराइजेशन, पंजीयन का भू-अभिलेखों के साथ एकीकरण, भू-कर मानचित्र का भू-अभिलेखों के साथ लिंकेज और आधुनिक रिकॉर्ड रूम।
- उल्लेखनीय है कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट प्रोग्राम केंद्र सरकार के शत-प्रतिशत वित्तपोषण से डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस द्वारा वर्ष 2008-9 से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से आधुनिक, विस्तृत और पारदर्शी भू-अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है।

नोट :

- कार्यक्रम के अंतर्गत जनवरी 2022 के बाद से अच्छा कार्य करने वाले ज़िलों को पुरस्कृत करने के लिये, उनके द्वारा कार्यक्रम के एमआईएस पर अंकित डाटा के आधार पर मंथली ग्रेडिंग प्रणाली लागू की गई है। इसमें 90% से 95% तक सिल्वर, 95% से 99% तक गोल्ड और 99% से अधिक कार्य दक्षता पर प्लैटिनम ग्रेड प्रदान की जाती है।

मेपकॉस्ट एवं एनआईएफ गांधीनगर के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर: मध्य प्रदेश में बनेगा स्टेट इनोवेशन फाउंडेशन

चर्चा में क्यों?

19 जुलाई, 2023 को म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मेपकॉस्ट) भोपाल और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गांधीनगर के बीच सहमति-पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गए, जिसके अंतर्गत दोनों संस्थानों के बीच जमीनी स्तर के नवाचार, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग के लिये प्रदेश में स्टेट इनोवेशन फाउंडेशन बनेगा।

प्रमुख बिंदु

- एमओयू पर म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया की ओर से निदेशक डॉ. अरविंद सी. रानाडे ने हस्ताक्षर किये।
- एमओयू का मुख्य उद्देश्य दोनों संस्थानों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में शोधकार्यों, नवाचारों, बौद्धिक संपदा अधिकारों और अकादमिक स्तर पर एक-दूसरे को सहयोग प्रदान करना है।
- मेपकॉस्ट के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी ने बताया कि राज्य में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की सहायता से स्टेट इनोवेशन फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इस कार्य में एन.आई.एफ. के विशेषज्ञों से तकनीकी सहायता ली जाएगी।
- स्टेट इनोवेशन फाउंडेशन की सहायता से प्रदेश के नवाचारियों का एक डेटाबेस निर्मित कर उनके उत्पादों को कमर्शियल करने में सहायता प्राप्त होगी।
- एमओयू के अंतर्गत इनोवेशन फाउंडेशन-विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शोधकार्य के लिये रिसर्च गाइड उपलब्ध कराएगा। ज़मीनी नवाचारों और बौद्धिक संपदा अधिकारों के जागरूकता अभियान के लिये तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराई जाएगी। पारंपरिक ज्ञान को मजबूत करने के लिये तकनीकी सहयोग किया जाएगा।
- इसी प्रकार रिसर्च स्कॉलर्स को दोनों संस्थानों में उपलब्ध रिसर्च इंस्ट्रूमेंटेशन एवं पुस्तकालय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। दोनों संस्थान संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के लिये संयुक्त रूप से परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

- यह एमओयू 3 वर्ष के लिये किया गया है। इसकी अवधि 2 वर्ष और बढ़ाई जा सकती है। इस एम.ओ.यू. से प्रदेश के नवाचारियों को उचित मंच प्राप्त होगा, जिसकी सहायता से वह अपने उत्पादों को पेटेंट में परिवर्तित करा सकेंगे। इसके लिये उन्हें उचित तकनीकी परामर्श एवं संसाधन प्रदान किये जाएंगे।
- डॉ. अनिल कोठारी ने बताया कि दोनों संस्थाओं के बीच विज्ञान लोकप्रियकरण की गतिविधियों, कार्यक्रमों और परियोजना प्रस्तावों को तैयार करने में परस्पर सहयोग किया जाएगा। इसी प्रकार वैज्ञानिक प्रकाशन के क्षेत्र में आदान-प्रदान किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि स्टडी प्रोग्राम, सेमिनार, सम्मेलन आदि के आयोजनों में परस्पर सहयोग किया जाएगा। साथ ही नवाचारी व्यक्तियों, अन्वेषकों और शोधार्थियों के लिये वैज्ञानिक विषयों और मुद्दों पर जानकारियों का साझा विनिमय किया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने उच्च न्यायालय और ज़िला न्यायालयों के लिये आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों ?

18 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ जबलपुर में मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। पोर्टल से उच्च न्यायालय की तीनों खंडपीठ और ज़िला न्यायालय की जानकारियाँ मिल सकेंगी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने बताया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय पूरे देश में प्रारंभ से अंत तक पेपरलेस मोड पर काम करने में अग्रणी है। पोर्टल को इंटीग्रेटेड क्लाउड बेस्ड बनाया गया, साथ ही इसे उच्च न्यायालय के डाटाबेस से भी इंटीग्रेटेड किया गया है।
- इस ऑनलाइन पोर्टल को सभी प्रकार के ऑनलाइन लेन-देन के लिये साइबर ट्रेजरी से भी जोड़ा गया है।
- मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि यह पोर्टल आरटीआई में चाही गई जानकारी को उपलब्ध कराने के लिये संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों की ज़िम्मेदारी को तय कर उन्हें जबाबदेह बनाता है।
- यह सॉफ्टवेयर न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mphc.gov.in के ई-आरटीआई टैब पर राज्य के लोक सूचना अधिकारी और संबंधित स्टाफ को, आरटीआई के संबंध में होने वाली ऐसी प्रत्येक गतिविधि की जानकारी, जो आवेदक द्वारा चाही गई है, एक क्लिक पर उपलब्ध कराता है।

राज्यपाल ने 'चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश' संस्करण के तहत प्रदेश के 16 उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया

चर्चा में क्यों ?

19 जुलाई, 2023 को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के सभागार में आयोजित 'चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश' संस्करण के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में अध्यात्म, समाज-कल्याण, कला, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल के क्षेत्र की 16 उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अध्यात्म के क्षेत्र में पं. प्रदीप मिश्रा, समाज-कल्याण के क्षेत्र में पं. ओम प्रकाश मेहता, विधायक कृष्णा गौर, हेमंत तिवारी, उमाशंकर सिंह, विनोद कुमार अग्रवाल, अपर पुलिस महानिदेशक अन्वेष मंगलम, रोहित जैन, मनोज साहू, अभिषेक कुमार पांडे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पद्मश्री डॉ. मुनिश्वर चंद्र डावर, डॉ. अजय राणा, कला के क्षेत्र में फिल्म अभिनेत्री सौम्या टंडन, फिल्म निर्देशक अनिल सिह चंदेल, शिक्षा के क्षेत्र में जयनारायण चौकसे और खेल के क्षेत्र में पावर लिफ्टर भावना टोकेकर को सम्मानित किया।
- चैंपियंस ऑफ चेंज के संस्थापक नंदन कुमार झा ने बताया कि कार्यक्रम मध्य प्रदेश संस्करण का दूसरा अवार्ड समारोह है। समारोह का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर चार बार किया गया है। मध्य प्रदेश सहित चार राज्यों में राज्य स्तरीय कार्यक्रम किये गए हैं। शीघ्र ही अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि 'चैंपियंस ऑफ चेंज (सीओसी)' सामुदायिक सेवा, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता जैसे भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिये एक भारतीय पुरस्कार है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी।
- चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकॉनमी (IFIE) संस्था, भारत सरकार द्वारा देश में चिह्नित कुल 115 आशावादी ज़िलों में गांधीवादी मूल्यों (स्वच्छता), सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास को अपने सकारात्मक प्रयासों से बढ़ावा देने वाले राजनेता, सामाजिक कार्यकर्त्ता, उद्यमियों को दिया जाता रहा है।
- इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकॉनमी संस्था प्रतिवर्ष भारत में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार का आयोजन करता है। इस अवार्ड को आमतौर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या भारत के एक प्रमुख व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
- पुरस्कार विजेताओं का चयन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और एनएचआरसी के पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में शीर्ष संवैधानिक जूरी सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकॉनमी संस्था भारत सरकार से मान्यता प्राप्त (80G, 8A के अनुरूप), गैर-लाभकारी कंपनी है, जो महात्मा गांधी के मूल्यों को बढ़ावा देने वाले 115 आकांक्षात्मक ज़िलों सहित ग्रामीण भारत की महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के लिये समर्पित है।

- 'चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश' पुरस्कार साहस, सामुदायिक सेवा और समावेशी सामाजिक विकास के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिये एक राज्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर शुरू किया गया है। पुरस्कार विजेताओं का चयन न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा (सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश) की अध्यक्षता में संवैधानिक जूरी के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

नागदा बनेगा प्रदेश का नया ज़िला

चर्चा में क्यों?

20 जुलाई, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन ज़िले की तहसील नागदा में विकास पर्व के दौरान कुल 261 करोड़ 14 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि-पूजन/लोकार्पण किया और नागदा को ज़िला बनाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि विकास पर्व में प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में विकास कार्यों का लोकार्पण/शिलान्यास किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ने नागदा में 92 करोड़ 61 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 168 करोड़ 53 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया।
- मुख्यमंत्री ने नागदा क्षेत्र की बहु-प्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए इसे ज़िला बनाए जाने की घोषणा की। उज्जैन ज़िले की जो तहसीलें नागदा में स्वेच्छा से मिलना चाहें, उन्हें ही नागदा में सम्मिलित किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि उज्जैन से अलग होकर नागदा प्रदेश का 54वाँ ज़िला बनेगा। इसके पहले रीवा ज़िले के मऊगंज तहसील को ज़िला बनाए जाने की घोषणा की जा चुकी है। फिलहाल मध्य प्रदेश में 52 ज़िले हैं, लेकिन नागदा और मऊगंज को ज़िले में परिवर्तित करने से 54 ज़िले हो जाएंगे।
- वर्तमान में नागदा, उज्जैन ज़िले की एक तहसील है। महाभारत का युद्ध जीतने वाले पांडवों के इतिहास में नागदा का उल्लेख मिलता है। बताया गया है कि इस स्थान में पांडवों के पौत्र राजा जन्मेजय द्वारा नागों के दाह के लिये एक विशाल यज्ञ किया गया था, इसीलिये इस नगर का नाम नागदा हुआ।
- इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कई अन्य घोषणाएँ भी कीं-
  - उन्हेल को तहसील बनाया जाएगा और यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे।
  - नागदा, खाचरोद, आलोट में सी. एम. राइज स्कूल खोले जाएंगे।
  - नर्मदा का पानी क्षिप्रा के साथ ही गंभीर और कालीसिंध नदियों में पहुँचाया जाएगा।

नोट :

म.प्र. राज्य जूनियर ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 27 जुलाई से 7 अगस्त तक

चर्चा में क्यों ?

20 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य जूनियर ई-स्पोर्ट्स 27 जुलाई से 7 अगस्त, 2023 तक आयोजित किया जाएगा।।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि मध्य प्रदेश में देश की पहली ई-स्पोर्ट्स अकादमी शुरू होने जा रही है। इसके लिये मध्य प्रदेश राज्य जूनियर ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के माध्यम से टैलेंट सर्च किया जाएगा।
- इस चैंपियनशिप में 12 से 17 वर्ष के युवा भाग ले सकते हैं। चयनित ई-स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को 12 महीने का प्रशिक्षण नि:शुल्क दिया जाएगा।
- मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने मध्य प्रदेश में दो ऐसे नए अकादमी खोलने की घोषणा की है, जो आगामी ओलंपिक और एशियन गेम्स का हिस्सा होंगी। इस बार ब्रेक-डांस को खेलों के रूप में शामिल किया गया है।
- प्रदेश में प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय बी बॉयर करीम और भारत के मशहूर बी बॉयर आरिफ चौधरी हर ज़िले में टैलेंट सर्च कर नई प्रतिभाओं का चयन कर रहे हैं।
- ई-स्पोर्ट्स के लिये जूनियर चैंपियनशिप के द्वारा टैलेंट सर्च में खेल विभाग द्वारा 80 प्रतिशत सीट प्रदेश के खिलाड़ियों के लिये तथा 20 प्रतिशत सीट राज्य के बाहर के लिये खिलाड़ी निर्धारित है।
- ई-स्पोर्ट्स गेमिंग को कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स के रूप में पदक जीतने वाले खेल की श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्द्धाओं में शामिल किया गया है। वर्ष 2022 में बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय टीम ने कांस्य पदक हासिल किया था। सितंबर में शुरू होने वाले एशियन गेस्म में भी ई-स्पोर्ट्स शामिल है।

पचमढ़ी मैराथन के पाँचवें संस्करण का हुआ सफल आयोजन

चर्चा में क्यों ?

23 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड (एमपीटीबी) और ज़िला प्रशासन नर्मदापुरम के सहयोग से 'एडवेंचर एंड यू'(के.ए. कनेक्ट) द्वारा पचमढ़ी मानसून मैराथन के पाँचवें संस्करण का सफल आयोजन हुआ। इस मैराथन में देशभर से 1350 धावकों ने भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

पचमढ़ी मानसून मैराथन के पाँचवें संस्करण में चार वर्ष के बच्चे से लेकर 75 वर्ष के बुजुर्ग ने ऊर्जा और उत्साह के साथ दौड़ लगाई।

- धावकों ने पचमढ़ी के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एवं 5 किलोमीटर श्रेणियों में दौड़ लगाई।
- मैराथन दौड़ एमपीटी ग्लेनव्यू होटल से शुरू हुई। समापन में विजेताओं को सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और मेडल दिये गए।
- प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति और प्रबंध संचालक टूरिज़्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि पचमढ़ी मैराथन की सफलता को देखते हुए खजुराहो में भी 11 फरवरी, 2024 को मैराथन का आयोजन होगा। पचमढ़ी में ही 17 दिसंबर को एक अल्ट्रा मैराथन (30, 60 ओर 90 किलोमीटर) होने जा रही है।
- मैराथन के विजेता
  - 42 किलोमीटर (पुरुष) में प्रथम विजेता पी. सेल्वन
  - 42 किलोमीटर (महिला) में प्रथम विजेता निकिता मंडलोई
  - 21 किलोमीटर (पुरुष) में प्रथम विजेता रमनजीत
  - 21 किलोमीटर (महिला) में प्रथम विजेता युविका मेरोथेन
  - 10 किलोमीटर (पुरुष) में प्रथम विजेता दत्ता कुमार

नोट :

- 10 किलोमीटर (महिला) में प्रथम विजेता कविता शर्मा
- 5 किलोमीटर (पुरुष) में प्रथम विजेता संभव मिश्रा
- 5 किलोमीटर (महिला) में प्रथम विजेता दिव्यांशी

5वाँ हेलिकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन खजुराहो में आयोजित किया जाएगा

चर्चा में क्यों?

23 जुलाई, 2023 को पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 5वाँ हेलिकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 25 जुलाई को मध्य प्रदेश के खजुराहो में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम का विषय 'अंतिम मील तक पहुँचना: हेलिकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी' है।
- इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रारूप में एक उद्घाटन सत्र और उसके बाद एक तकनीकी सत्र शामिल हैं।
- शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों में उड़ान योजना के विस्तार को बढ़ाना है।
- शिखर सम्मेलन के व्यापक उद्देश्य हैं:
- सभी उद्योग हितधारकों और नीति निर्माताओं के लिये भारतीय हेलिकॉप्टर और लघु विमान उद्योग के विकास की कहानी पर चर्चा करने के लिये एक साझा मंच प्रदान किया जाए।
- सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों में उड़ान योजना का विस्तार बढ़ाएँ और देश की ग्रामीण से शहरी कनेक्टिविटी का प्रसार करें।
- वर्तमान व संभावित पर्यटन हॉटस्पॉट वाले स्थलों पर हेलिकॉप्टर और लघु विमान की कनेक्टिविटी को निर्बाध सेवाएँ प्रदान करके बढ़ावा देना।
- हेलिकॉप्टर और लघु विमान भारत के परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागरिक हेलिकॉप्टर विशेषत: दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर पहुँच में योगदान करते हैं, पर्यटन के लिये जबरदस्त संभावनाएँ प्रदान करते हैं, जिससे यात्रियों को अद्वितीय तरीकों से सुंदर परिदृश्य और सांस्कृतिक स्थलों का अनुभव प्राप्त होता है। हेलिकॉप्टर सेवा की अन्य भूमिकाओं में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ और बाढ़ के दौरान आपदा प्रबंधन, बचाव अभियान आदि शामिल हैं।

- इसी तरह लघु विमान, व्यवसाय और अवकाश यात्रियों के लिये कुशल और सुविधाजनक परिवहन का विकल्प प्रदान करते हैं, क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं और अल्प-ज्ञात गंतव्यों की खोज को बढ़ावा देते हैं। विमानन और पर्यटन उद्योग परस्पर एक-दूसरे से लाभान्वित होते हैं, रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देते हैं और पूरे देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं।
- शिखर सम्मेलन ऐसे महत्त्वपूर्ण समय पर हो रहा है, जब भारतीय नागरिक उडन्यन उद्योग एक आदर्श परिवर्तन के समय से गुजर रहा है। यह क्षेत्र अब न केवल भारत के लिये बल्कि दुनिया भर में मानव जाति के लिये समय की मांग बन गया है, क्योंकि यह हमेशा अपने साथ दो महत्त्वपूर्ण गुणक लाता है- आर्थिक गुणक और रोज़गार गुणक।
- 5वाँ हेलि शिखर सम्मेलन उद्योग हितधारकों को नीति निर्माताओं के साथ जुड़ने और सहयोग करने के लिये एक साथ लाएगा, जिससे सक्षम और विवेकपूर्ण निर्णयों को लागू किया जाए, जो भारत के नागरिक उड्डयन उद्योग को और अधिक विस्तार देगा।

एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना से 218.98 मेगावाट विद्युत क्रय करने का किया अनुबंध

चर्चा में क्यों ?

21 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने गुजरात के काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना से 218.98 मेगावाट विद्युत क्रय करने का एक पावर परचेस एग्रीमेंट गत दिवस हस्ताक्षरित किया।

प्रमुख बिंदु

- इस पावर परचेस एग्रीमेंट पर एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक (कमर्शियल-पारंपरिक) शैलेंद्र जनार्दन और न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना के डायरेक्टर एस.के. राय ने हस्ताक्षर किये।
- विदित है कि भारत की प्रथम स्वदेश निर्मित 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को गुजरात के काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना (यूनिट-3) में स्थापित किया गया है। इस यूनिट ने 30 जून, 2023 को वाणिज्यिक विद्युत उत्पादन प्रारंभ कर दिया है।
- इस परियोजना की यूनिट-4 से अगले वर्ष फरवरी 2024 से विद्युत उत्पादन प्रारंभ होने की संभावना है।

- भारत के न्यूक्लियर ऊर्जा कार्यक्रम में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इससे देश की बढ़ती हुई ऊर्जा मांगों को स्वच्छ और भरोसेमंद न्यूक्लियर ऊर्जा के माध्यम से पूरा करने में मदद मिलेगी। पावर मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा किये गए पावर परचेस एग्रीमेंट में मध्य प्रदेश को भी बिजली की आपूर्ति होगी।
- परमाणु विद्युत-पावर परचेस एग्रीमेंट में मध्य प्रदेश को यह बिजली मात्र रुपए 4.40 पैसे प्रति यूनिट (सिंगल पार्ट टेरिफ) की दर से 30 जून से सतत् (24×7) रूप से सस्ती दर पर प्राप्त होने लगी है। काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना से प्राप्त होने वाली यह बिजली प्रदेश के उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय करने में उपयोगी सिद्ध होगी।

फिट इंडिया क्विज 2022 में शिवपुरी पब्लिक स्कूल के दो छात्र हुए सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

23 जुलाई, 2023 को बांद्रा, मुंबई स्थित बीकेसी में केंद्रीय युवा मामले, खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी पब्लिक स्कूल 2 छात्रों को फिट इंडिया क्विज स्टेट राउंड के दूसरे एपिसोड में उनकी सफलता पर सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि अनुराग सिंह ठाकुर ने मध्य प्रदेश सहित 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 72 स्कूली छात्रों को फिट इंडिया क्विज स्टेट राउंड के दूसरे एपिसोड में उनकी सफलता पर सम्मानित किया।
- ये 72 छात्र अपने-अपने राज्य में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले हैं और अब फिट इंडिया क्विज के राष्ट्रीय दौर में प्रतिस्पर्द्धा करेंगे, जो स्टार स्पोर्ट्स और डिज़्नी हॉटस्टार पर प्रसारित किया जाएगा।
- फिट इंडिया प्रतियोगिता 2022 में शिवपुरी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स दिव्यांश गाला एवं अनिरुद्ध यादव ने स्टेट फाइनल में जीत हासिल करके ज़िले का गौरव बढ़ाया।
- प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के विजेता स्कूल को कुल 2.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिली, जबकि स्कूल के 2 छात्रों की टीम को कुल 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया।
- राज्य प्रथम रनर-अप स्कूल को 1 लाख रुपए और छात्रों को कुल 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि मिली। इसी प्रकार स्टेट सेकेंड रनर-अप स्कूल को 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार मिला और भाग लेने वाले छात्रों को कुल 5,000 रुपए का पुरस्कार मिला।
- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश दौर के लिये कुल 348 स्कूलों और 418 छात्रों का चयन किया गया था। इन छात्रों में 39% छात्राएँ थीं। चयनित स्कूलों ने दो छात्रों की एक टीम बनाई, जिन्होंने वेब राउंड की एक सीरीज के जरिये राज्य/केंद्र शासित प्रदेश चैंपियनशिप के लिये प्रतिस्पर्द्धा की। 36 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश चैंपियनों की पहचान के लिये कुल 120 राउंड आयोजित किये गए। राज्य/केंद्रशासित प्रदेश चैंपियन के रूप में पहचाने गए 36 स्कूलों में से 12 सरकारी स्कूल हैं।
- स्कूलों के लिये फिट इंडिया नेशनल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स क्विज का दूसरा संस्करण पिछले साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस की पूर्व संध्या पर अनुराग सिंह ठाकुर और राज्य मंत्री, युवा मामले और खेल और गृह मंत्रालय निसिथ प्रामाणिक द्वारा केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया था।
- फिट इंडिया क्विज के दूसरे संस्करण में भारत के 702 ज़िलों के 16,702 स्कूलों के 61,981 छात्रों की भारी भागीदारी देखी गई है। इसकी तुलना में, फिट इंडिया क्विज के पहले संस्करण में 13,502 स्कूलों के कुल 36,299 छात्रों ने भाग लिया। पहले संस्करण की तुलना में क्विज के दूसरे संस्करण में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या में 70% की बढ़ोतरी देखने को मिली।
- गौरतलब है कि फिट इंडिया क्विज स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये खेल और फिटनेस पर भारत की सबसे बड़ी क्विज है। स्कूली बच्चों के बीच फिट इंडिया के संदेश को प्रचारित करने और स्कूलों में इसकी उपस्थिति को मज़बूत करने के उद्देश्य से 2020 में क्विज का शुभारंभ किया गया था।
- फिट इंडिया क्विज, फिट इंडिया मूवमेंट का एक हिस्सा है, जिसका शुभारंभ 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस पहल का उद्देश्य भारत को एक फिट और स्वस्थ राष्ट्र बनाना।
- क्विज में कुल 3.25 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार स्कूल और छात्रों को प्रदान किये जाते हैं। यह देश के हर कोने से छात्रों को खेल और फिटनेस में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने और राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय दौर के बाद विजेता स्कूल को कुल 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी, जबकि प्रथम उपविजेता और दूसरे उपविजेता स्कूल को क्रमशः 15 लाख रुपए और 10 लाख रुपए मिलेंगे।

नोट :

भोपाल में बनेगा राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय

चर्चा में क्यों ?

24 जुलाई, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की महा-परिषद की बैठक में जानकारी दी गई कि भोपाल में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्वविद्यालय में केंद्रीय स्टूडियो, डिजिटल मीडिया लैब, सिनेमा और भारतीय भाषाओं पर केंद्रित पृथक विभागों तथा भरतमुनि शोध पीठ की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।
- जनवरी 2018 के बाद हुई महा-परिषद की बैठक में पूर्व वर्षों के बजट अनुमान, लेखों एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया। विभिन्न प्रबंधकीय विषयों पर भी निर्णय लिये गए।
- बैठक में बताया गया कि एशिया के पहले और देश के सबसे बड़े पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू किया गया है। इंडिया टुडे, द वीक जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं द्वारा विश्वविद्यालय को देश के प्रथम 10 शिक्षण संस्थानों में शामिल किया गया है।
- महा-परिषद ने विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिये 7वाँ वेतनमान लागू करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। साथ ही 01 जनवरी, 2016 से लागू किये गए 7वें वेतनमान के आधार पर सभी शिक्षकों को एरियर का भुगतान करने की स्वीकृति भी दी गई।
- संविदा पर कार्यरत शिक्षकों के नियमितिकरण पर भी सहमति हुई। महा-परिषद ने अधि-वार्षिकी आयु को 60 से 62 वर्ष किये जाने पर भी अनुमोदन प्रदान किया।
- बैठक में विश्वविद्यालय के बिशनखेड़ी स्थित नवीन परिसर में विद्यार्थियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिये रेडियो कर्मवीर की स्थापना को भी स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही शोध पुस्तक लेखन, पी-एचडी पाठ्यक्रम में सीट वृद्धि संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
- बैठक में बताया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्यूनिकेशन, यू.एन. पॉपुलेशन फंड, महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ कम्यूनिकेशन कोजीकोड केरल, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल नई दिल्ली तथा अन्य विश्वविद्यालयों और प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ एम.ओ.यू. किये गए।

नोट :

प्रदेश में लॉजिस्टिक पार्क, फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण, रेलवे वेगन निर्माण और पीवीसी केंद्रित इकाइयों की स्थापना के प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

24 जुलाई, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से फार्मालॉजिस्टिक पार्क, खाद्य प्र-संस्करण, आयरन एंड स्टील तथा प्लास्टिक के क्षेत्र में कार्यरत उद्योग समूहों ने मंत्रालय में भेंट कर प्रदेश में निवेश और इकाइयों के विस्तार के संबंध में चर्चा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से टीवीएस इंडस्ट्रीज एंड लॉजिस्टिक्स पार्क के सीईओ रामनाथ सुब्रमण्यम और रीजनल हेड कुशल मोतियानी ने देवास और पीथमपुर में 250 करोड़ रुपए की लागत से इंडस्ट्रियल व लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की। पार्क से लगभग 1000 लोगों के लिये रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।
- प्रदेश में फार्मा क्षेत्र में 1300 करोड़ रुपए की लागत से तीन इकाइयाँ स्थापित कर चुकी इप्का लेबोरेट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजित कुमार जैन ने मुख्यमंत्री से भेंट कर देवास में 470 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित हो रही फार्मा इकाई के बारे में बातचीत की। इस इकाई में लगभग 700 लोगों को रोज़गार मिलेगा।
- मुख्यमंत्री से सात्त्विक एग्रो प्रोसेसिंग के नीलेश गर्ग और माणिक गर्ग ने मुरैना ज़िले के सीतापुर में नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के संबंध में चर्चा की। सात्त्विक एग्रो 284 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश के साथ एक लाख 44 हज़ार मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता के साथ नई इकाई स्थापित कर रही है। कंपनी द्वारा इसके लिये भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है।
- सर्वा फोम के कुणाल ज्ञानी रायसेन ज़िले के तामोट प्लास्टिक पार्क में 100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ रिबांडेड फोम और पालियोरेथेन फोम के लिये बुनियादी कच्चा माल बनाने की इकाई की स्थापना के प्रस्ताव और अपेक्षाओं पर चर्चा की।
- मुख्यमंत्री से हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रा-स्ट्रक्चर के राघवेंद्र मोदी ने मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में 500 करोड़ के निवेश और लगभग 1000 लोगों को रोज़गार देने की क्षमता रखने वाली रेलवे वेगन निर्माण इकाई स्थापित करने के संबंध में बातचीत की।
- इसी क्रम में बैरलोकर इंडिया एडिटिव्स के ज्येन मोदी और श्री अंकुर कुमार ने देवास में 316 करोड़ रुपए के निवेश से पीवीसी स्टेबलाइजर इकाई की स्थापना पर बातचीत की। इकाई से लगभग 150 लोगों को रोज़गार मिलेगा।

नोट :

मध्य प्रदेश के खजुराहो में तीन उड़ान प्रशिक्षण संगठनों का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

25 जुलाई, 2023 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में तीन उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ) का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- खजुराहो में तीन एफटीओ खुलने से मध्य प्रदेश में कुल एफटीओ की संख्या छह हो जाएगी- खजुराहो में तीन, इंदौर में एक, सागर में एक और गुना में एक। ये छ: एफटीओ युवाओं द्वारा क्षेत्र के विकास में योगदान सुनिश्चित करने का प्रमुख माध्यम बनेंगी।
- इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने शीघ्र ही खजुराहो से वाराणसी के बीच वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की सेवा आरंभ करने की घोषणा भी की।
- मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि पिछले नौ वर्षों में देश में हवाई अड्डे, जल हवाई अड्डे और हेलीपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर 148 हुई, जिसे आने वाले 4 सालों में हम 200 से अधिक कर पाएंगे। वहीं विमान क्षमता 400 से बढ़कर 700 हुई है, यानी 75% वृद्धि हुई है, जिसे हम आने वाले चार से पाँच सालों में 1200 से 1500 तक ले जा पाएंगे।'
- उन्होंन बताया कि 2016 में देश में केवल 28 फ्लाइंग अकादमी थी, जो अब बढ़कर 57 हो गई है। पिछले वर्ष 1135 कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस नागर विमानन निदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी किये गए जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। इस वर्ष मात्र पाँच महीनों में वह संख्या बढ़ कर 731 हो गई है।''
- इंडियन फ्लाइंग एकेडमी: इंडियन फ्लाइंग एकेडमी शौर्य फ्लाइट सिम प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा की गई 'आत्मनिर्भर भारत'पहल के तहत खजुराहो हवाई अड्डे पर स्थापित की गई है।
  - इसने 05 विमान अधिगृहित किये हैं, जिनमें से 04 पहले ही आ चुके हैं। इन 04 विमानों में से 03 विमान एकल-इंजन विमान हैं जिनमें दो डायमंड डीए 40, एक इवेक्टर और एक मल्टी इंजन विमान-डायमंड डीए 42 शामिल हैं।
  - भारतीय फ्लाइंग अकादमी में प्रति बैच उड़ान प्रशिक्षण के लिये 40 छात्रों की क्षमता होगी और एफटीओ में प्रति वर्ष 2 बैच होंगे।
- फ्लाईओला एविएशन एकेडमी (जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड) - हेलीकॉप्टर एफटीओ: फ्लाईओला एविएशन एकेडमी हेलीकॉप्टर एफटीओ एशिया का पहला वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर पायलट लाइसेंस (सीएचपीएल) प्रशिक्षण संस्थान है। फ्लाईओला एविएशन एकेडमी के बेड़े में वर्तमान में दो रॉबिंसन आर 44 हेलीकॉप्टर हैं और एक समय में उड़ान प्रशिक्षण के लिये 20 छात्रों की क्षमता है।
- फ्लाईओला एविएशन एकेडमी (जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड) - फिक्स्ड विंग एफटीओ: फ्लाईओला एविएशन अकादमी का फिक्स्ड विंग एफटीओ मल्टी-इंजन प्रशिक्षण विमान पर प्रशिक्षण दे रहा है जिसे उच्च प्रदर्शन वाला विमान माना जाता है। फ्लाईओला एविएशन एकेडमी के ट्रेनर बेड़े में शामिल हैं: -
- फ्लाईओला एविएशन एकेडमी एक बैच में 20 कैडेट्स को प्रशिक्षित कर सकती है। इसके लिये एफटीओ के पास 04 फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं।

खजुराहो में हेलीशिखर सम्मेलन 2023 और उड़ान 5.2 का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

25 जुलाई, 2023 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। साथ ही आरसीएस उड़ान 5.2 और हेली सेवा-ऐप को भी लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- इस 5वें हेलीकॉप्टर एवं लघुविमान शिखर सम्मेलन (हेलीशिखर सम्मेलन 2023) का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के सहयोग से संयुक्त रूप से किया गया।
- इस कार्यक्रम का विषय 'रीचिंग द लास्ट माइल: रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट' यानी 'दूर-दराज तक पहुँच: हेलीकॉप्टर एवं छोटे विमानों के जरिये क्षेत्रीय कनेक्टिविटी' था।
- इस कार्यक्रम के दौरान एक उद्घाटन सत्र और उसके बाद एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया।
- इस शिखर सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
  - भारतीय हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान उद्योग के विकास गाथा पर चर्चा करने के लिये उद्योग के सभी हितधारकों और नीति निर्माताओं के लिये एक साझा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना।
  - सुदूर एवं पहाड़ी इलाकों में उड़ान योजना का दायरा बढ़ाना और देश में ग्रामीण से शहरी कनेक्टिविटी का विस्तार करना।
  - निर्बाध सेवाएँ उपलब्ध कराते हुए मौजूदा एवं संभावित पर्यटन हॉटस्पॉट के लिये हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के जरिये कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना।
- इस अवसर पर उड़ान 5.2 को देश में दूरदराज के क्षेत्रों एवं क्षेत्रीय इलाकों में कनेक्टिविटी को बेहतर करने और 1ए (<9 सीट) एवं श्रेणी 1 (<20 सीट) जैसे छोटे विमानों के जरिये अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिये लॉन्च किया गया है।
- मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि हेलीकॉप्टर के लिये उड़ान 5.2 की शुरुआत की गई है और इसके तहत वीजीएफ में वृद्धि और फेयर कैप को कम किया गया है। इसी के साथ हेली सेवा का सिंगल विंडो सेवा प्लेटफॉर्म भी आरंभ किया गया है।
- मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम के दौरान हेली-सेवा मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया।
- उल्लेखनीय है कि हेली सेवा पोर्टल डिजिटल इंडिया के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक पहल है। इसके तहत हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों और जिला अधिकारियों के बीच एक परिवेश तैयार करने के लिये एक साझा प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है।
- यह मोबाइल एप्लीकेशन इसे उपयोगकर्ता अनुभव, सामग्री अपलोड करने और उपयोग करने के लिहाज से कहीं अधिक सुविधाजनक बना देगा।
- इस अवसर पर भारत में हेलीकॉप्टर और लघु विमान क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिये पवनहंस और जेट सर्व के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किये गए।

म.प्र. के 11 खिलाड़ी करेंगे चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व

चर्चा में क्यों ?

26 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में 11 अलग-अलग विधाओं के खिलाड़ी चेंगडू (चीन) में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसमें नौ खिलाड़ी मध्य प्रदेश की विभिन्न अकादमी से हैं।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी ऑफ एक्सीलेंस के समर दीप सिंह, निधि पवैया, शालिनी चौधरी (सभी बरकतउल्ला विश्वविद्यालय) अर्जुन वास्कले (एसएनसिटी विश्वविद्यालय), एमपी फेंसिंग अकादमी ऑफ एक्सीलेंस के शंकर (रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय रायसेन), अंकित शर्मा (लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय) तथा मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी ऑफ एक्सीलेंस के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और आशी चौकसे (दोनों गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर) और चिंकी यादव (बरकतउल्ला विश्वविद्यालय) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- मध्य प्रदेश की नंदनी वत्स (रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय) और कुमारी अंतिम यादव (लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, फगवाड़ा) जूडो में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने सभी खिलाड़ियों से टीटी नगर स्टेडियम में मुलाकात कर शुभकामनाएँ दीं।

म.प्र. श्रम कल्याण मंडल के संचालक मंडल का गठन

चर्चा में क्यों ?

26 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश शासन श्रम विभाग द्वारा म.प्र. श्रम कल्याण मंडल का गठन किया गया है। गठित संचालक मंडल में अध्यक्ष भगवानदास गोंडाने तथा सचिव कल्याण आयुक्त (पदेन) मनोनीत किया गया।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा उपसचिव म.प्र. शासन, श्रम विभाग रत्नाकर झा को मंडल के कल्याण आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
- संचालक मंडल में नियोजकों के 6 प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, जिनमें कार्यपालक निदेशक भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड भोपाल या प्रतिनिधि अतुल खंडेलवाल, नामा मुकुंद हरि (संचालक जारगो इंड. प्रा. लि एवं अध्यक्ष पीथमपुर उद्योग संचालक संगठन, पीथमपुर ज़िला धार), चंद्रप्रकाश आवतानी (उप-महाप्रबंधक (एच.आर.) भागीरथ कोच एंड मेटल फेडीकेटर, इंदौर), आई.के. कोचर (अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, रतलाम इकाई, रतलाम), सी.एम.डी. के.पी. सोल्वेक्स प्रा.लि., निवाड़ी तथा अमित शर्मा (कार्यकारी अध्यक्ष जयप्रकाश एसोसिएट लि., जे.पी. नगर, रीवा) सम्मिलित है।
- संचालक मंडल में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों में अरविंद मिश्रा (प्रदेश उप महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, म.प्र. ग्वालियर), कमलेश पटेल (प्रदेश मंत्री भारतीय मजदूर संघ, म.प. कटनी), संगीता श्रीवास्तव (महामंत्री, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ, भारतीय मजदूर संघ,

म.प्र. टीकमगढ़), आर.डी. त्रिपाठी (अध्यक्ष, म.प्र. इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्ग्रेस भोपाल), दीपक जायसवाल (राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, भोपाल) एवं रामविलास गोस्वामी (प्रदेश अध्यक्ष, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस लश्कर, ग्वालियर) शामिल हैं।

- संचालक मंडल में 7 स्वतंत्र सदस्य मनोनीत किये गए हैं, जिनमें प्रमुख सचिव म.प्र. शासन श्रम विभाग, भोपाल, श्रमायुक्त म.प्र. शासन, इंदौर, संचालक कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ इंदौर, सामाजिक कार्यकर्ता (स्वच्छता अभियान प्रेरक) प्रताप करोसिया (इंदौर), श्याम, सामाजिक कार्यकर्ता (उपभोक्ता जागरण मंच, इंदौर प्रमुख) सुंदर चौकसे, सामाजिक कार्यकर्ता एवं व्यवसायी अमृत जैन (इंदौर) एवं डॉ. मंजू जरोलिया (जबलपुर) शामिल है।

मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय बढ़कर 1,40,583 रुपए हुई

चर्चा में क्यों?

- 28 जुलाई, 2023 को केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपने अद्यतन आँकडे जारी किये जिनमें पता चला है कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय विगत तीन वर्षों में 1,03,654 रुपए से बढ़कर 1,40,583 हुई है।

प्रमुख बिंदु

- देश के प्रगतिशील राज्यों के साथ मध्य प्रदेश में आज की प्रचलित दरों के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि निश्चित ही आर्थिक प्रगति का एक शुभ संकेत है।
- मध्य प्रदेश के स्थिर भावों (वर्ष 2011-12) के आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2021-22 (त्वरित) में 61,534 रुपए थी, जो बढ़कर वर्ष 2022-23 (अग्रिम) में रुपए 65,023 हो गई है, जो गत वर्ष की तुलना में 5.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
- प्रचलित भावों के आधार पर राज्य की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2021-22 में 1,21,594 रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 (अग्रिम) में 1,40,583 हो गई, जो 15.62 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
- वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021-22 (त्वरित) की तुलना में प्रचलित भावों पर 16.43 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर 7.06 प्रतिशत की वृद्धि रही है।
- राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भावों पर वर्ष 2022-23 अग्रिम के दौरान विगत वर्ष से प्राथमिक क्षेत्र में 5.24 प्रतिशत, द्वितीयक एवं तृतीय क्षेत्र में क्रमश: 5.42 प्रतिशत एवं 9.99 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि रही है।
- प्रधानमंत्री द्वारा भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प में मध्य प्रदेश द्वारा 550 बिलियन डॉलर का योगदान देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश इस लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में तेज़ी से कार्य कर रहा है।
- प्रदेश के बजट का आकार भी वर्ष 2001-02 की तुलना में पंद्रह गुना बढ़कर वर्ष 2023 में 2,47,715 करोड़ रुपए हो गया है।
- राज्य द्वारा लगातार राजकोषीय अनुशासन का निरंतर पालन करने से वर्ष 2005 का ऋण जीएसडीपी अनुपात जो वर्ष 2005 में 395 प्रतिशत था वह घटकर 22.6 प्रतिशत रह गया है, यानी कर्ज़ का भार कम हुआ है।
- मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि प्रदेश में बेहतर वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय समावेशन जैसे अर्थव्यवस्था के मूलभूत आधारों का परिणाम है।
- साथ ही प्रदेश में सरकारी बैंकिंग व्यवसाय में निरंतर वृद्धि, प्राथमिकता क्षेत्र के समय पर समुचित ऋण, जन-धन खातों में आमजन की बढ़-चढ़कर भागीदारी और बचत, प्रदेश में जन-आंदोलन का स्वरूप ले चुके स्व-सहायता समूहों द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सतत् योगदान भी इसके प्रमुख कारकों में हैं।
- इसके अलावा कृषि-प्रधान प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि, छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ औद्योगीकरण के चौतरफा प्रयासों से बढ़ते निवेश की भी प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

- बिजली क्षेत्र में सरप्लस स्टेट होना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़कों के नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार तथा स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा किये गए सुविचारित प्रयास भी प्रदेश की इस महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के पीछे हैं।

मध्य प्रदेश एक बार फिर बना टाइगर स्टेट

चर्चा में क्यों ?

29 जुलाई, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में सर्वाधिक 785 बाघ मध्य प्रदेश में हैं, जिनकी वजह से प्रदेश को पुन: टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश में पिछले चार वर्षों में बाघों की संख्या 526 से बढ़कर 785 हो गई है। इसके बाद दूसरे स्थान पर कर्नाटक (563) और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड (560) है।
- मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अग्रणी है। मध्य प्रदेश तेंदुआ और घड़ियाल स्टेट भी है। गिद्ध और भेड़ियों की संख्या में भी प्रदेश आगे है।
- इस अवसर पर प्रदेश में बाघ संरक्षण पर सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व पर केंद्रित फिल्म दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने फिल्म के कलाकारों को स्मृति-चिह्न प्रदान किये।
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन विभाग के शासकीय सेवकों को उत्कृष्ट कार्य के लिये प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए।
- वन विभाग के कर्मचारियों को सरवाइवल किट भी दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के ई-टिकटिंग एवं मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी किया।
- इस ऐप से पर्यटकों को अब घर से ही ऑनलाइन टिकट बुक करने की सुविधा मिलेगी। ऐप पर वन विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध रहेगी।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय वन्य-प्राणी कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट, स्टेट वाईल्ड लाइफ एक्शन प्लान तथा फिफ्थ बर्ड्स सर्वे रिपोर्ट ऑफ गांधी सागर वाईल्ड लाइफ सेंचुरी (मंदसौर) सहित तीन पुस्तक का विमोचन किया।

The Vision

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी प्रशिक्षण के लिये ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस रवाना

चर्चा में क्यों ?

- 30 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने राजभवन से अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के विद्यार्थियों की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

- विश्व बैंक और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वित्तीय सहयोग से संचालित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के संस्थान विकास कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के 18 विद्यार्थी चयनित हुए हैं। इनमें से 8 विद्यार्थी ऑस्ट्रेलिया में और 10 विद्यार्थी फिलीपींस के उच्च कृषि शिक्षा संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिये वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया जाने वालों में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय ग्वालियर से निखिल खरे, कशिश यादव, शिवराज सिंह पोसवाल, आलोक चतुर्वेदी, कृषि महाविद्यालय सीहोर से तनु सिसौदिया, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर से सुरभि आचार्य और कृषि महाविद्यालय, इंदौर से निकिता सोलंकी तथा आदेश कनेल शामिल हैं।
- वहीं आई.आर.आर.आई. मनीला फिलीपींस जाने वालों में कृषि महाविद्यालय ग्वालियर से स्नेहा विश्वास, स्नेहा शर्मा, सुरंजना कुमारी, प्राजिक्ता कटारे, कृषि महाविद्यालय इंदौर से जयदीप पाठक, मुनीरा कौसर अंसारी, मरीना वी.एल., कृषि महाविद्यालय सीहोर से श्रुति तोमर, कृषि महाविद्यालय खंडवा से अनुराग शर्मा और उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर से गार्गी त्रिपाठी शामिल हैं।